व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना का कार्यान्वयन

501. चौधरी हरमोहन सिंह यादव:
श्री ईश दत्त यादव:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु एक व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना सफल रही है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्य नारायण जटिया): (क) जी, हां। सरकार एक व्यावसायिक (न कि वृत्तिक) प्रशिक्षण परियोजना को कार्यान्वित कर रही है।

(ख) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, शिक्षुता प्रशिक्षण योजना तथा अन्य सम्बद्ध योजनाओं के तहत प्रशिक्षण गतिविधियों को आधुनिकीकरण एवं उन्नयन करने हेतु, विश्व बैंक की सहायता से एक व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना (वी टी पी) 1989 में आरम्भ की गई थी जिसमें 28 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था तथा जिसकी बुनियादी लागत 441 करोड़ रु॰ थी। यद्यपि परियोजना का समापन वस्तुत: 1996 में किया जाना था तथापि, इसकी अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई जिससे कि चल रही गतिविधियों का समुचित प्रकार से समापन किया जा सके। परियोजना के प्रमुख घटकों का समापन दिसम्बर, 1997 में हुआ। दिसम्बर, 1997 में विश्व बैंक ने निजी सिफारिश पर आरम्भ किए गए घटकों सहित कुछ चुनिन्दा घटकों के एक और वर्ष अर्थात् दिसम्बर, 1998 तक निधिकरण जारी रखने हेतु अपनी सहमति की सूचना दी।

(ग) विश्व बैंक मिशन ने जनवरी-फरवरी 1998 में एक संयुक्त समीक्षा की जिससे यह स्पष्ट हुआ कि राज्य क्षेत्रों में लगभग समस्त वस्तुपरक उपलब्धियां प्राप्त कर ली गई हैं, यद्यपि, कुछ केन्द्रीय क्षेत्र के घटक निर्धारित समय से पीछे रहे। कुछ राज्यों का कार्य-निष्पादन बहुत अच्छा रहा तथा उन्होंने निर्धारित लक्ष्यों की सीमा भी पार की ली। अध्ययन से आई टी आई प्रमाण-पत्र धारकों के रोजगार पर परियोजना का प्रत्यक्ष प्रभाव भी परिलक्षित हुआ है जिसका श्रेय उपलब्ध कराई गई उन्नत सुविधाओं एवं प्रशिक्षण को दिया गया है।

(घ) सरकार का परियोजना के लाभों के समेकन तथा पहले से ही आरम्भ की गई गतिविधियों को स्वदेशी संसाधनों के माध्यम से जारी रखने का विचार है।

देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के बाद रोजगार पर प्रभाव

502. चौधरी हरमोहन सिंह यादव:
श्री ईश दत्त यादव:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के बाद बेरोजगारी पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्री (डा. सत्य नारायण जटिया): (क) से (ग) बेरोजगारी पर बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के प्रभाव की जानकारी हेतु कोई विशेष अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है। तथापि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा पंचवर्षीय सर्वेक्षण पर आधारित रोजगार/बेरोजगारी आंकड़े दर्शाते हैं कि श्रम बल की बेरोजगारी दर जो 1987-88 में 3.77 प्रतिशत थी, सामान्य रूप से मुख्य स्तरीय दृष्टिकोण के अनुसार 1993-94 में घट कर 2.56 प्रतिशत रह गई है।

Setting up of a New National Labour Commission

503. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the leading Trade Union Organisations and Employers' Organisations have demanded setting up of a new National Labour Commission; and

(b) if so, the details thereof and what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Yes, Sir.

(b) Labour Laws have been enacted over a period of time to address a number of issues which assumed importance and attracted pointed attention at a particular point of time. While many of these issues are of continued nature, some of these might have ceased to be of importance, hence the need for review of Labour policies, programmes and laws flowing from them. This question has also been discussed in the Tripartite meeting of the Standing Labour Committee and Indian Labour Conference and the Government has agreed, in principle, to have these laws reviewed by setting up a high powered body so as to ensure consistency of

labour laws with the general changes taking place in the economic policy as also to provide for greater welfare of the working class.

Increase in the wages of the workers under minimum wages act

504. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been an all out increase in the salaries of Government servants whereas there has been no such increase in the monthly wages of the workers coming under Minimum Wages Act;-and

(b) if so, what action Government propose to take to ensure increase in the monthly wages of the workers in the organised and unorganised sectors with immediate effect?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Yes, Sir. There has been an increase in the salaries of Central Government employees w.e.f. January 1, 1996 following acceptable by Government of the recommendations of the Fifth Central Pay Commission.

(b) Wages in the organised sector are largely determined through bipartite negotiation and settlements. The wages in the scheduled employments in the unorganised sector are fixed & revised under the Minimum Wages Act, 1948. The State Governments/U.T. administrations have been requested to revise wages for scheduled employments under the Minimum Wages Act, every two years or on a rise of 50 points in Consumer Pricer Index number, whichever is earlier.

Workers partnership in unorganised and organised sectors

505. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether any survey has been undertaken in respect of workers in unorganised sector to increase their partnership with the organised sector workers;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, whether Government proposed to do so to increase nation's production?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) At present there is no such proposal.

Unemployment in the Country

506. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the total number of unemployed youth in the country as on 31st March, 1998 as per the enrolment made in the live register of the states and the Central Employment Exchanges;

(b) whether Government have drawn up any time bound programme to remove unemployment from the country; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) The number of job-seekers, all of whom are not necessarily unemployed, who were on the live register of employment exchanges in the country as on 28th February, 1998 (latest data available) was 390.67 lakh.

(b) and (c) The approach to the Ninth Plan envisages priority to agriculture and rural development with a view to generating adequate productive employment and eradication of poverty.

Greater productive employment will be generated in the growth process itself by concentrating on sectors and sub-sectors and technologies which are labour intensive, in regions characterized by higher rater of unemployment and underemployment.

देश में बाल श्रम

507. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री रामगोपाल यादव:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में ऐसे कुल कितने बाल श्रमिक हैं जिनकी आयु 14 वर्ष या इससे कम है;

(ख) सरकार ने अब तक इनमें से कितने बाल श्रमिकों को मुक्त करा कर उनके भोजन, आवास और शिक्षा संबंधी उचित सुविधाओं का प्रबंध किया है; और

(ग) शेष बाल श्रमिकों को मुक्त करा कर उन्हें समुचित जीवन जीने का अवसर मुहैया कराए जाने संबंधी समयावधि और सरकारी कार्यक्रम क्या है?